111

Suggestion another copy submitted to moderator

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS" Zone : M

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	S.P. Sharma + Rawat - DTS.
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Buddhvihar K.V. S.R. 19873 Harsh Dev Park II.
वर्तमान स्थिति Present Position	Colony Rikarbin . . P.
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9891307744 (9811617467) H.No. D-32. Harsh Dev Park Buddhvihar Phase II, Delhi-110086
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	A/164 20 H.D. Park Budh II Delhi 86.
हस्ताक्षर : Signature :	S.P. Sharma
तिथि : Date :	1/5/12

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3023
Dated 11/5

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

A/E/20 A-3, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No. BVKVS/10/21 Dated : 28/12/10

सेवा में,

आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री
भारत सरकार
पब्लिक शिकायत कक्ष
रेल भवन नई दिल्ली

29/12/10

विषय: हर्षदेव पार्क कालोनी को नियमिती कराने के संबध में पत्र

महोदय

निवेदन यह है कि हर्षदेव पार्क कालोनी 1.1.1981 से पहले बसी हुई कालोनी है दिल्ली के अति. टाउन प्लानर माननीय ओ.पी.मलिक जी ने 30.5.89 को एन.ओ.सी जारी करके कालोनी का नक्शा बुनियादी सुविधा के लिए जारी किया था ।

इसी के आधार पर बुद्धविहार विकास संघ ट्रांसफर जमीन 100 वर्ग गज से लेकर विधुत्ती करण कराने मे सफल हुआ तथा पूर्व विधायक जी द्वारा दो रोडो पर खढंजा भी लगाया गया था तथा दो रोडो पर नाली भी बनाई गई थी ।

विधुत्तीकरण का नेट वर्क 17.3.97 तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री साहिब सिंह वर्मा व स्व. श्री के. एल. शर्मा सांसद की मौजुदगी में उद्घाटन सहारोह सम्पन्न हुआ था ।

बुद्धविहार कल्याण विकास संघ के प्रधान एस.पी. शर्मा 1992 से आज तक कार्यकारणी एंव जनता को साथ लेकर विकास कार्य कराते आए है । जिसका रिकार्ड सरकार के पास भी है तथा रजिस्टार आफिस में भी है ।

दिल्ली सरकार द्वारा 2005 में युसी सैल ने कालोनियां की जानकारी मांगी थी उस समय श्री दयानन्द सोंलकी पूर्व प्रधान जिन्होंने कालोनी काटी थी उन्हाने टाउन प्लानर द्वारा छोडा हुआ हिस्सा भी शामिल करके नक्शा शहरी विभाग में 31.1.05 रजि. 398 के तहत जमा करा दिया । प्रमाण पत्र भी झूठा पेश किया गया सामुदाय भवन एंव पार्क भी दिखाया गया जबकि सामुदाय भवन जमीन बेच दी गई पार्क की जगीन शपथ पत्र के बाद बेच दी गई संघ द्वारा विरोध करने पर कालोनाइजर होने के नाते अनसुनी कर दी गयी ।

दिल्ली सरकार द्वारा पुनः 2007 में युसी विभाग द्वारा तमाम दिल्ली की कालोनियों को कहा गया कि आप अपना सारा रिकार्ड वास्तविक कार्यस्थली के साथ जमा कराये । उस समय बुद्धविहार कल्याण विकास संघ द्वारा 28.12.07 रिसीव पत्र 864 के साथ सी.डी. व नक्शें जमा कराये गये थें ।

दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की गई कि रामलीला मैदान में युसी विभाग की लिस्ट द्वारा माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्राविज़नल सर्टीफ़िकेट बांटे जायेगे ।

दिल्ली शहरी विभाग युसी सेल मे तैनात श्री जे.सी. अरोड़ा डिप्टी सेकेट्री द्वारा मालुम हुआ कि आपकी कालोनी की फाईल के साथ अन्य कालोनी की फाईल जमा हो गयी है जिसका कारण आपकी कालोनी को प्रोविजनल सर्टीफिकेट नही दिया जायेगा ।

9891307744

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

~~A-87~~ A1-20 HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041
9891307744
9811617467

Ref. No. BVKVS/10/30 Dated : 28/12/10

सेवामें

श्रीमान कमिश्नर

स्पेशल सचिव (UC)

शहरी विभाग दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

विषय- हर्ष देव पार्क कॉलोनी को (नियमितीकरण) के सम्बन्ध में ÷

मान्यवर आपके द्वारा पत्र संख्या 16265-68 - dt० 11/10/10 को जारी फाइल में हर्ष देव पार्क कॉलोनी (द्वारा UC सैल रजि० 1398) के संदर्भ में प्राप्त हुआ।

महोदय आप को अवगत कराना चाहते कि जबसे हमें मालूम हुआ है तभी से हम अपनी कालोनी के बारे में UC सैल के तमाम अधिकारियों से लेकर आप तक वास्तविक जानकारी पेश करते रहे हैं मगर आज तक यह दीदावर दिखाया है कि एक रजिस्ट्रियत लेकर आया। हम हमेशा फर्जी रजिस्ट्रियत लेकर पेश हुए मगर आप के द्वारा आपका फाइल जमा करने बाद हमें परेशानी में डाला गया है, आप ही इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।

आप ही बताओ हम किस-किस व्यक्ति से कहेंगे कि आप अपनी फाइल वापिस करके हम हमेशा UC द्वारा जारी रजिस्ट्रियत लेकर 30/12/89 से पैरवी कर रहे हैं ना हमने कभी क्षेत्र देखा ना ही कभी हम छोड़े क्षेत्र को मिलायेंगे यदि किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा मिलाने की बात की जाती है तो सबसे पहले मिलाने वाले क्षेत्र की जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल करना जरूरी है।

87/85/UC

महोदय आपसे प्रार्थना है कि निष्पक्ष जाँच रजिस्ट्री विभाग इस मामले की जाँच करके उचित निर्णय करें। हम उच्चतम न्यायालय से माननीय मुख्य सचिव साहब भी फैसला दे चुके हैं।

कृपा के लिए धन्यवाद।

भवदीय

(एन० पी० शर्मा) (प्रधान)

हर्ष देव पार्क

28/12/10 X

28/12/10

28/12/10

9891307744

507

(111)

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

~~A-3~~, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
O- A1-20- BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No. BVKVS. 32/2012 Dated : 1/5/12.

सेवामें,

श्रीमान संबन्धित अधिकारी महोदय
डि.वि.प्र. दिल्ली

विषय- हर्ष देव पार्क 1398 कालोनी के विषय में पत्र-

मान्यवर निवेदन है कि हर्षदेव पार्क कालोनी 1981 जनवरी के पहले बसी कालोनी है 17/3/97 को बिजली सुविधा भी मिल चुकी है महोदय 2895 Politican का मेजर फैसला माननीय डी.के. जैन एवं एम.के. सीकरी न्यायाधीश उच्चन्यायालय द्वारा जनवरी 2004 में कालोनी हित में आने के बाद में आजतक भी कालोनी को नियमित कालोनियों की सूची में नहीं ई. और नहीं कोई योजना गई क्रिया नहीं पत की गयी है मकान बनाते समय डी.डी.ए., पुलिस, MCD द्वारा सभी कर्मचारी मकान बनाने में परेशानी खड़ी करते हैं।

महोदय आपसे प्रार्थना है कि आप 80 हजार आबादी के क्षेत्र में एक समुदाय भवन, डिस्पेन्सरी, स्कूल बगैरह बुनियादी सुविधा दिलाने की सुविधा दें तथा पानी सीवर की व्यवस्था बनाने में हर प्रकार सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद.

एस.पी. शर्मा
प्रधान
हर्षदेव पार्क
9891307744
9811617467

Total copy 10 + m.c. copy

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

~~A-3~~, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
A1-20 BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

111

Ref. No. BVKVS 32/2012 Dated : 1/5/12.

सेवामें

श्रीमान सम्बन्धित अधिकारी महोदय
डी.वि.प्र. दिल्ली

विषय- हर्ष देव पार्क 1398 कालोनी के विषय में पत्र-

मान्यवर निवेदन है कि हर्षदेव पार्क कालोनी 1981 जनवरी से पहले बसी कालोनी है 17/3/97 को बिजली सुविधा मिल चुकी है मेघदूत 2895 Petition का मेजर फैसला माननीय डी.के. जैन एवं एम.के. सीकरी न्यायाधीश उच्चन्यायालय द्वारा जनवरी 2004 में कालोनी हित में आने के बाद में आजतक भी कालोनी को नियमित कालोनियों की सूची में नहीं लिया है. और नाही कोई योजना लिखित की गयी है मकान बनाते समय डी.डी.ए., पुलिस, MCD द्वारा सभी कर्मचारी मकान बनाने में परेशानी खड़ी करते हैं।

मेघदूत में माननीय न्यायालय ने है कि 10 हजार आबादी के क्षेत्र में दिलाने की सुविधा दें तथा पानी सीवर की व्यवस्था बनाने में हर प्रकार सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद

(एस.पी. शर्मा)
प्रधान
हर्षदेव पार्क
9891307744
9811617467

510

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

A/1/20 A-3, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No._____ Dated : 28/12/10

संघ द्वारा दूसरा पत्र आदरणीय श्री राजकुमार चौहान विकास मंत्री दिल्ली सरकार को 19.9.08 को दिया मगर मंत्री महोदय के यहॉ से भी कोई न्याय नही दिया गया ना ही कोई पत्र द्वारा बुलाया गया ।

संघ द्वारा तीसरा पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को भी पत्र द्वारा शिकायत की गई 15.7.2010 तारीख से अभी तक कोइ काय्रवाही नही की गई ।

संघ द्वारा चौथा पत्र श्रीमती कृष्णा तीर्थ जी केन्द्रिय मंत्री भारत सरकार को भी पत्र 9.7.10 को दिया गया वहॉ से भी आज तक न्याय नही मिला है । स्थानीय विधायक जी से लेकर दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव युसी विभाग तक आज तक हमारी कालोनी को नियमतिकरण में कोई काय्रवाही नही की गई है ।

महोदय आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी कालोनीं के साथ जमा कालोनियों की जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बिठाकर जानकारी हासिल कराने की कृपा करे तथा धोखेबाजो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने की कृप्या करे । कुछ लोगो ने दो–दो जगह अपने को दिखा रखा है ।

हमें आशा है कि आप हमारी शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही कराने की कृप्या करेगे ।

धन्यवाद सहित

भवदीय

एस.पी.शर्मा (प्रधान)
बुद्धविहार कल्याण विकास संघ
बुद्ध विहार फेज-II, दिल्ली-110
9891307744
9811617467

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

Pr 1/20 ~~A-3,~~ HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No. BVKVS/10/22 Dated : 28/12/10

RAJ NIWAS
Sign.:
Date 29/12/10
DELHI

सेवा मे,

आदरणीय तजेन्द्र खन्ना जी,
उपराजयपाल
दिल्ली सरकार
राजनिवास दिल्ली

विषय: हर्षदेव पार्क कालोनी को नियमिती करने के संबन्ध में पत्र

महोदय,

निवेदन यह है कि हर्षदेव पार्क कालोनी 1.1.1981 से पहले बसी हुई कालोनी है दिल्ली के अति. टाउन प्लानर माननीय ओ.पी.गलिक जी ने 30.5.89 को एन.ओ.सी. जारी करके कालोनी का नक्शा बुनियादी सुविधा के लिए जारी किया था ।

इसी के आधार पर बुद्धविहार विकास संघ ट्रांसफर जमीन 100 वर्ग गज से लेकर विधुत्ती करण कराने मे सफल हुआ तथा पूर्व विधायक जी द्वारा दो रोडो पर खढंजा भी लगाया गया था तथा दो रोडो पर नाली भी बनाई गई थी ।

विधुत्तीकरण का नेट वर्क 17.3.97 तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री साहिब सिंह वर्मा व स्व. श्री के. एल. शर्मा सांसद की मौजुदगी में उद्घाटन सहारोह सम्पन्न हुआ था ।

बुद्धविहार कल्याण विकास संघ के प्रधान एस.पी. शर्मा 1992 से आज तक कार्यकारणी एंव जनता को साथ लेकर विकास कार्य कराते आए है । जिसका रिकार्ड सरकार के पास भी है तथा रजिस्टार आफिस में भी है ।

दिल्ली सरकार द्वारा 2005 में युसी सैल ने कालोनियों की जानकारी मांगी थी उस समय श्री दयानन्द सोंलकी पूर्व प्रधान जिन्होने कालोनी काटी थी उन्हाने टाउन प्लानर द्वारा छोड़ा हुआ हिस्सा भी शामिल करके नक्शा शहरी विभाग में 31.1.05 रजि. 1398 के तहत जमा करा दिया । प्रमाण पत्र भी झुठा पेश किया गया समुदाय भवन एंव पार्क भी दिखाया गया जबकि समुदाय भवन जमीन बेच दी गई पार्क की जमीन शपथ पत्र के बाद बेच दी गई संघ द्वारा विरोध करने पर कालोनाइजर होने के नाते अनसुनी कर दी गयी ।

दिल्ली सरकार द्वारा पुनः 2007 में युसी विभाग द्वारा तमाम दिल्ली की कालोनियों को कहा गया कि आप अपना सारा रिकार्ड वास्तविक कार्यस्थली के साथ जमा कराये । उस समय बुद्धविहार कल्याण विकास संघ द्वारा 28.12.07 रिसीव पत्र 864 के साथ सी.डी. व नक्शें जमा कराये गये थें ।

दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की गई कि रामलीला मैदान में युसी विभाग की लिस्ट द्वारा माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्राविजनल सर्टीफिकेट बांटे जायेगे ।

दिल्ली शहरी विभाग युसी सेल मे तैनात श्री जे.सी. अरोड़ा डिप्टी सेकेट्री द्वारा मालुम हुआ कि आपकी कालोनी की फाईल के साथ अन्य कालोनी की फाईल जमा हो गयी है जिसका कारण आपकी कालोनी को प्रोविजनल सर्टीफिकेट नही दिया जायेगा ।

संघ द्वारा प्रधान सचिव युसी विभाग को शिकायत पत्र 13.8.08 को दिया गया जिसका आज तक कोई जवाब नही मिला है काउटंर नं.-4 सचिवालय में जिला प्रतिनिधी बुलावे मे दिया गया था ।

S.P. Sharma
9891307744

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

A1/20 ~~A-3~~, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No._____ Dated : 28/12/10

संघ द्वारा दूसरा पत्र आदरणीय श्री राजकुमार चौहान विकास मंत्री दिल्ली सरकार को 19.9.08 को दिया मगर मंत्री महोदय के यहॉ से भी कोई न्याय नही दिया गया ना ही कोई पत्र द्वारा बुलाया गया ।

संघ द्वारा तीसरा पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को भी पत्र द्वारा शिकायत की गई 15.7.2010 तारीख से अभी तक कोइ काय्रवाही नही की गई ।

संघ द्वारा चौथा पत्र श्रीमती कृष्णा तीर्थ जी केन्द्रिय मंत्री भारत सरकार को भी पत्र 9.7.10 को दिया गया वहॉ से भी आज तक न्याय नही मिला है । स्थानीय विधायक जी से लेकर दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव युसी विभाग तक आज तक हमारी कालोनी को नियमतिकरण में कोई काय्रवाही नही की गई है ।

महोदय आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी कालोनीं के साथ जमा कालोनियों की जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बिठाकर जानकारी हासिल कराने की कृपा करे तथा धोखेबाजो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने की कृप्या करे । कुछ लोगो ने दो–दो जगह अपने को दिखा रखा है ।

हमें आशा है कि आप हमारी शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही कराने की कृप्या करेगे ।

धन्यवाद सहित

भवदीय

S.P.Sharma

एस.पी.शर्मा (प्रधान)
बुद्धविहार कल्याण विकास संघ
9891307744
9811617467

S.P.Sharma
9891307744

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANGH (REGD.)

A1/20 ~~A-3~~, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No. BVKV S/10/23 Dated : 28/12/10

सेवा मे,

आदरणीया श्रीमती कृष्णा तीर्थ जी,
महिला एंव बाल विकास राज्य मंत्री
भारत सरकार सरकार
8 तुगलक,लेन नई दिल्ली

विषयः हर्षदेव पार्क कालोनी को निःमिती कराने के संबध में पत्र

महोदय,

निवेदन यह है कि हर्षदेव पार्क कालोनी 1.1.1981 से पहले बसी हुई कालोनी है दिल्ली के अति. टाउन प्लानर माननीय ओ.पी.मलिक जी ने 30.5.89 को एन.ओ.सी. जारी करके कालोनी क. नक्शा बुनियादी सुविधा के लिए जारी किया था ।

इसी के आधार पर बुद्धविहार विकास संघ ट्रांसफर जमीन 100 वर्ग गज से लेकर विधुत्ती करण कराने मे सफल हुआ तथा पूर्व विधायक जी द्वारा दो रोडो पर खढंजा भी लगाया गया था तथा दो रोडो पर नाली भी बनाई गई थी ।

विधुत्तीकरण का नेट वर्क 17.3.97 तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री साहिब सिंह वर्मा व स्व. श्री के. एल. शर्मा सांसद की मौजुदगी में उद्घाटन सहारोह सम्पन्न हुआ था ।

बुद्धविहार कल्याण विकास संघ के प्रधान एस.पी. शर्मा 1992 से आज तक कार्यकारणी एंव जनता को साथ लेकर विकास कार्य कराते आए है । जिसका रिकार्ड सरकार के पास भी है तथा रजिस्टार आफिस में भी है ।

दिल्ली सरकार द्वारा 2005 में युसी सैल ने कालोनियों की जानकारी मांगी थी उस समय श्री दयानन्द सोंलकी पूर्व प्रधान जिन्होने कालोनी काटी थी उन्हाने टाउन प्लानर द्वारा छोड़ा हुआ हिस्सा भी शामिल करके नक्शा शहरी विभाग में 31.1.05 रजि. 1398 के तहत जमा करा दिया । प्रमाण पत्र भी झुठा पेश किया गया समुदाय भवन एंव पार्क भी दिखाया गया जबकि समुदाय भवन जमीन बेच दी गई पार्क की जमीन शपथ पत्र के बाद बेच दी गई संघ द्वारा विरोध करने पर कालोनाइजर होने के नाते अनसुनी कर दी गयी ।

दिल्ली सरकार द्वारा पुनः 2007 में युसी विभाग द्वारा तमाम दिल्ली की कालोनियों को कहा गया कि आप अपना सारा रिकार्ड वास्तविक कार्यस्थली के साथ जमा कराये । उस समय बुद्धविहार कल्याण विकास संघ द्वारा 28.12.07 रिसीव पत्र 864 के साथ सी.डी. व नक्शें जमा कराये गये थें ।

दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की गई कि रामलीला मैदान में युसी विभाग की लिस्ट द्वारा माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्राविजनल सर्टीफिकेट बांटे जायेगे ।

दिल्ली शहरी विभाग युसी सेल मे तैनात श्री जे.सी. अरोड़ा डिप्टी सेकेट्री द्वारा मालुम हुआ कि आपकी कालोनी की फ़ाईल के साथ अन्य कालोनी की फाईल जमा हो गयी है जिसका कारण आपकी कालोनी को प्रोविजनल सर्टीफिकेट नही दिया जायेगा ।

संघ द्वारा प्रधान सचिव युसी विभाग को शिकायत पत्र 13.8.08 को दिया गया जिसका आज तक कोई जवाब नही मिला है काउटंर नं.-4 सचिवालय में जिला प्रतिनिधी बुलावे मे दिया गया था ।

S.P. Sharma
9891307744

29/12/2010
(minister)

506

BP Sharma
9811307749

UNDER CERTIFICATE OF POSTING

Shri Daya Nand,
S/o Shri Bharat Singh,
A / 4, Harsh Dev Park,
Budh Vihar,
New Delhi

500

BUDH VIHAR KALYAN VIKAS SANCH (REGD.)
A-1/20 A-3, HARSH DEV PARK P.O. POOTH KALAN, POOTH, RITHALA ROAD,
BUDH VIHAR, PHASE - II, DELHI - 110 041

Ref. No._____ Dated : 28/12/10

संघ द्वारा दूसरा पत्र आदरणीय श्री राजकुमार चौहान विकास मंत्री दिल्ली सरकार को 19.9.08 को दिया मगर मंत्री महोदय के यहॉ से भी कोई न्याय नही दिया गया ना ही कोई पत्र द्वारा बुलाया गया ।

संघ द्वारा तीसरा पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को भी पत्र द्वारा शिकायत की गई 15.7.2010 तारीख से अभी तक कोइ काय्रवाही नही की गई ।

संघ द्वारा चौथा पत्र श्रीमती कृष्णा तीर्थ जी केन्द्रिय मंत्री भारत सरकार को भी पत्र 9.7.10 को दिया गया वहॉ से भी आज तक न्याय नही मिला है । स्थानीय विधायक जी से लेकर दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव युसी विभाग तक आज तक हमारी कालोनी को नियमतिकरण में कोई काय्रवाही नही की गई है ।

महोदय आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी कालोनीं के साथ जमा कालोनियों की जमीन की वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बिठाकर जानकारी हासिल कराने की कृपा करे तथा धोखेबाजो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने की कृप्या करे । कुछ लोगो ने दो-दो जगह अपने को दिखा रखा है ।

हमें आशा है कि आप हमारी शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही कराने की कृप्या करेगे ।

धन्यवाद सहित

भवदीय

S.P.Sharma

एस.पी.शर्मा (प्रधान) बुद्धविहार कल्याण विकास संघ (रजि०) बुद्ध विहार फेज-II, दिल्ली 110

बुद्धविहार कल्याण विकास संघ

9891307744

9811617467

Educational and Industrial Trust Amritsar v. *State of Punjab & Ors.*, 1996 (4) SCC 212, the learned Judge has held that the land having been acquired and handed over to the DDA under Section 22(1) of the DDA Act, 1957, it stood vested in the DDA, the petitioner as such was left with no right in the property and his continued possession was illegal and unlawful.

7. This position was earlier re-affirmed, though in a different context, by a Division Bench of this Court in the case of *M/s. Prem Chand Ramesh Chand* v. *Delhi Development Authority & Anr.*, reported as 66 (1997) DLT 110 of which one of us (D.K. Jain, J.) was a member. It was held that a Notification under Section 4 or declaration under Section 6 of the Act cannot be invalidated merely on the ground that a policy decision had been taken by the Government to regularise the unauthorised colonies and petitioners structures would also be regularised. A similar view has been expressed by a Full Bench of this Court in the case of *Roshanara Begum* v. *Union of India*, reported in 61 (1996) DLT 206, which has since been upheld by the Supreme Court in *Murari Lal & Ors.* v. *Union of India & Ors.*, reported as 1997 (1) SCC 15. Nevertheless despite the above legal position, we cannot be oblivious of the hard reality staring at us that this colony, land in respect of which is sought to be acquired, is in existence for last more than thirty years and was in the list of the colonies which were to be regularised.

8. It is not a case of an individual or a few persons whose land is acquired and the acquisition is challenged on the ground that construction has been raised on the said land. Here is case where on the subject land a full fledged colony has come into existence. True that it was an unauthorised colony but the fact remains that a number of such colonies have sprung up in Delhi and the Government has been addressing itself as to how these unauthorised colonies have to be dealt with. Communication dated 16 February, 1977 addressed by the Ministry of Works & Housing, Government of India to the Lt. Governor of Delhi on the subject "Unauthorised colonies in Delhi approval of" itself mentions that the Government had appointed a Committee on 26 August, 1974 to make a case by case study in respect of unauthorised colonies which had come up in Delhi from time to time, in particular, before 15 June, 1972 with a view that the Government could take a decision in regard to the future of such colonies. The said Committee submitted its report on 26 February, 1975 which was examined by the Government and decision was taken to regularise these colonies on the terms and conditions set out therein. We are concerned with Condition No. 6 which reads as under:

"Colonies which have been notified for acquisition will also be considered for regularisation and wherever necessary other represential steps will be taken."

9. It is, thus, clear that it was in the contemplation of the Government that some of the colonies, in respect of which decision is taken to regularise them, are the ones which have been notified for acquisition. It was decided to take necessary steps for the purpose of such regularisation. Perhaps for this reason, no steps were taken to take possession of the land, although Notification under Section 4 in this case was issued on 11 December, 1981, with the result that these colonies, which came into existence in earlier 70s, are in existence for last more than 30 years.

SPS Lamm
9891307744.

10. It is pertinent to note that the land was sought to be acquired for the purpose of 'Planned Development of Delhi'. It appears that it was to be handed over to the DDA for some housing project and on the land in question houses already exist. No return is filed either by the Government or the DDA controverting these averments of the petitioners. Therefore, we have no option but to proceed on the basis that possession is still with the petitioners and there is no Notification under Section 22(1) of the Delhi Development Act, 1957 placing land at the disposal of the DDA.

11. In view of the factual scenario projected above, we are of the opinion that the ends of justice would be met if the writ petitions are disposed of with the following directions:

(I) While sustaining Notifications under Sections 4 and 6 of the Act, it is directed that the petitioners shall make appropriate representation to the Competent Authority under Section 48 of the Act for denotification of the land. On making such application within two weeks from the date of receipt of copy of this order, the respondents shall consider the same within six months from the date of making such representation.

(II) If the decision is taken to denotify the land, the Government shall be free to impose the conditions as are set out in communication dated 16 February, 1977 on which regularisation is to be done, *i.e.* with regard to lay out plan, provision for road and other community facilities, payment of development charges etc.

(III) Till such a decision is taken, the possession of the petitioners shall not be disturbed.

12. The writ petitions stand disposed of accordingly. No costs.

Writ Petitions disposed of.

D

MI

THE CITI

An Act further to an

Be it enacted by Par
follows:

1. *Short title and co*
(Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come int
notification in the Official

Provided that differe
and any reference in any
construed as a reference to

Assented by Preside
Extraordinary Part II, Secti

2. *Amendment of Secti*
(hereinafter referred to as t

(i) for Clauses (
shall be subs

'(b) "illega

(i) v
c
u

(ii) v
o
u
p

(ii) after Cl

'(ee) "

49a

Writ Petition
Under Judicial Department
High Court of Delhi

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

C.W.NO. 785 OF 1985

IN THE MATTER OF:

Shri Daya Nand & others ..... Petitioners

Versus

Union of India & others ..... Respondents

MEMO OF PARTIES

1. Daya Nand son of Bharat Singh, resident of A/4, Harsh Dev Park, Budh Vihar, New Delhi.
2. Kuldip Singh son of Bharat Singh, resident of A/13, Harsh Dev Park, Budh Vihar, New Delhi.
3. Muni Ram son of Prithvi Singh, resident of C-40, Harsh Dev Park, Budh Vihar, New Delhi.
4. Sukhbir Singh son of Prithvi Singh, resident of D-62, Harsh Dev Park, Budh Vihar, New Delhi.
5. Ajit Singh son of Bhagwan Singh, resident of A/1, Harsh Dev Park, New Delhi.
6. Milkhi Ram son of Nihalu Ram, resident of A/27, Harsh Dev Park, New Delhi.
7. B.S.Katodia son of Dhani Ram, resident of B-9, Harsh Dev Park, New Delhi.
8. Bhupinder son of Daya Nand, resident of B-2, Harsh Dev Park, New Delhi.
9. Lala Ram son of Babu Lal, resident of B/7, Harsh Dev Park, New Delhi.
10. Azad Singh son of Badlu Ram, resident of B/5, Harsh Dev Park, New Delhi.
11. Sher Singh son of Ganeshi, resident of A/21, Harsh Dev Park, New Delhi.
12. Bansi Dhar son of Krishan Singh, resident of A-40, Harsh Dev Park, New Delhi.
13. Banwari son of Rewati Ram, resident of A/23, Harsh Dev Park, New Delhi.
14. Shradanand son of Lakshmi Narain, resident of B-20, Harsh Dev Park, New Delhi.
15. Smt.Om Wati wife of Krishan Lal, resident of A-21-22, Harsh Dev Park, New Delhi.

BPSharma
9891307744

S. C. DHAMIJA
ADVOCATE

26, Lawyers Chambers,
Tehsil Building,
Tis Hazari Courts, Delhi- 110054
Phone : 3914522, 3935481

Office-cum-Residence
E- 35, Bali Nagar,
New Delhi-110015
Phone 5161116

U.P.C.

Ref. No.....

January 18, 2004

Shri Daya Nand,
S/O Shri Bharat Singh,
A/4, Harsh Dev Park,
Budh Vihar,
New Delhi

Subj: CIVIL WRIT PETITION NO.2895 of 1985
DAYA NAND AND OTHERS V/S UNION OF
INDIA & OTHERS.

Dear Sir:

This is to inform you that the above Writ has been disposed of by the Hon'ble High Court of Delhi, New Delhi, vide order dated 15-1-04.

The release of the land of Colony will depend upon the decision of the Government, with regard to the regularisation of the Colony. In case, the Colony is not regularised, you have a right to approach the Hon'ble High Court of Delhi, New Delhi against the decision of Government.

Thanking you,

Yours faithfully,

(S. C. DHAMIJA)
ADVOCATE:

BPSharma
9891307744

409

16. Smt: Kanta Devi wife of Lakshmi Narain resident of A/20, Harsh Dev Park, New Delhi.

17. Smt: Urmila Sahi wife of Paras Sahi, resident of Harsh Dev Park, New Delhi.

18. Smt: Radhika Devi wife of Sat Dev Tewari, resident of C-35, Harsh Dev Park, New Delhi.

19. Smt: Gian Devi wife of Om Parkash Sharma, resident of C-37, Harsh Dev Park, New Delhi.

20. Smt: Ram Jori wife of Kailash Rai, resident of C-33 Harsh Dev Park, New Delhi.

..... Petitioners.

Versus.

Union of India through
P.12 Secretary, Minstry of Works & Housing,
Nirman Bhawan,
New Delhi.

2. Delhi Development Authority,
through Secretary,
P.14 Vikas Minar,
I.P. Estate,
New Delhi.

3. Lt: Governor,
P.16 Raj Niwas Marg,
Delhi.

4. Land Acquisition Collector,
Tis Hazari Courts,
P.14 Delhi.

5. Commissioner,
Municipal Corporation of Delhi,
P.10 Town Hall,
Chandni Chowk,
Delhi.

..... Respondents.

Copy

NEW DELHI.

DATED: 23 .1985.

(S.C. DHANIJA)
ADVOCATE FOR THE PETITIONERS.

Certified to be True Copy
Judicial Department
High Court of Delhi
Authorised Under Section 76
Indian Evidence Act

TRUE COPY
EXAMINER

SPSharma
9891307744

Orders

08.01.2004
DAYA NAND & ANR. VS. UOI

Present: Mr.S.K.Rout , Adv.for the petitioner.
Mr.Sanjay Poddar, Adv.for the respondent.

CWP No.2895/1985

List on 15 January 2004.

Sd/-
D.K. JAIN, J.

January 08, 2004
mk

Sd/-
A.K.SIKRI, J.

TRUE COPY
EXAMINER

Certified to be True Copy
Judicial Department
High Court of Delhi
Authorised Under Section
Indian Evidence Act

SPSharma
9891307744

112 (2004) DELHI LAW TIMES 957 (DB)

DELHI HIGH COURT

D.K. Jain & A.K. Sikri, JJ.

DAYA NAND (SHRI) AND ORS. —Petitioners

versus

UNION OF INDIA & ORS. —Respondents

CWP Nos. 2895 and 2902 of 1985—Decided on 30.1.2004

Constitution of India, 1950 — Article 226 — Land Acquisition Act, 1894 — Sections 4, 6 — Delhi Development Act, 1957 — Section 22(1) — Notification under Sections 4 and 6 issued pertaining to village Poothkalan : Regularisation of unauthorised colonies : Petitioner claim theirs being unauthorised colony, acquisition proceedings to be quashed : No return filed by Goverment or DDA controverting averments of petitioner : Possession still with petitioners and there is no notification under Section 22 (1), DDA Act : Directions issued to meet ends of justice.

[Paras 9 to 11]

Result : Writ Petitions disposed of.

Cases referred:

1. 2002 (65) DRJ 313. *(Referred)* *[Para 4]*
2. 1996 (4) SCC 212. *(Relied)* *[Para 6]*
3. 66 (1997) DLT 110. *(Relied)* *[Para 7]*
4. 61 (1996) DLT 206. *(Relied)* *[Para 6]*
5. 1997 (1) SCC 15. *(Relied)* *[Para 7]*

Counsel for the Parties :

For the Petitioners : *Mr. S.K. Rout, Advocate.*

For the Respondents : *Mr. Sanjay Poddar and Mr. Sachin Nawani, Advocates.*

JUDGMENT

D.K. Jain, J.—In both these writ petitions, challenge is to the notifications issued under Sections 4 and 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (hereinafter referred to as 'the Act') in respect of the land pertaining to the same village, namely, Poothkalan popularly known as Mange Ram Park, Harshdev Park Extension of Budh Vihar, Delhi. Notification under Section 4 is No. F.9(16)/80-L & B dated 11 December 1981 and declaration under Section 6 was issued on 16 April 1984.

2. The stand of the petitioners is that the erstwhile owners converted this land into plots and sold the same to various persons, including the petitioners, much before the issuance of the aforesaid Notifications. The petitioners built up their houses, rooms, structures and boundary walls thereupon; they are in actual physical possession of the land and houses standing thereon and are actually living and residing there. It is also pleaded that over the land, subject matter of acquisition proceedings, a colony known as Budh Vihar, Phase-II has already come up. It is

argued that, on the one hand the land is sought to be acquired and on the other hand, a decision has been taken by the Government of India, Ministry of Works and Housing to consider regularisation of this colony. Reference in this respect is made to the orders dated 16 February, 1977 and 3 July, 1982. Order dated 16 February, 1977 (Annexure P-1), *inter alia*, records that the Government had appointed a Committee on 26 August, 1974 to make a case by case study in respect of all unauthorised colonies which have come up in Delhi, particularly before 15 June, 1972 with a view to take a decision in regard to the future of such colonies. The Committee submitted its report on 26 February, 1975 which was examined by the Government and it was decided that various unauthorised colonies which had come up in Delhi, including those around villages outside the *lal dora* as also the unauthorised extensions of approved colonies from time to time would be regularised on the terms and conditions set out therein. Para 6 of the terms and conditions stipulates that colonies which have been notified for acquisition, would also be considered for regularisation and wherever necessary, other steps would be taken.

3. The case of the petitioners, therefore, in nutshell, is that since the colony in question is one of the unauthorised colonies in respect of which decision was taken to regularise on terms and conditions contained in the aforesaid circulars, the acquisition proceedings are liable to be quashed.

4. On the other hand, Mr. Poddar, learned Counsel for the respondents has submitted that on the basis of the aforesaid decision, the petitioners cannot challenge the validity of Notification under Sections 4 and 6 of the Act, which were issued in exercise of statutory powers and are thus, statutory in nature. It is submitted that the Act is a complete Code in itself and once Notifications under Sections 4 and 6 of the Act have been issued, the land, subject matter of acquisition, could be released, before its possession is taken, only by passing an appropriate Order/Notification under Section 48 of the Act. In support, he has referred to a decision of a learned Single Judge of this Court in the case of *Moolchand Gaur* v. *Delhi Development Authority & Ors.*, reported in 2002 (65) DRJ 313, wherein many other judgments of this Court as well as of the Supreme Court on the issue have been noted and considered.

5. In so far as the legal position is concerned, we are unable to accept the submission of learned Counsel for the petitioners that merely because on the subject land an unauthorised colony has come up and now a decision has been taken to regularise it, the acquisition proceedings are rendered illegal and are, therefore, liable to be quashed.

6. A policy decision simplicitor has no statutory force and cannot negate the decision taken by the Government in exercise of its statutory powers contained in the Act for acquisition of land. Thus, there is no legal basis for challenging Notifications under Sections 4 and 6 of the Act issued respectively on 11 December, 1981 and 16 April, 1984 acquiring the land in question, on the ground that the colony is now proposed to be regularised. The legal position in this respect is succinctly explained by a learned Single Judge of this Court in the case of Moolchand Gaur (supra). Relying on the decision of the Apex Court in the case of *Balmokand Khatri*

SPSHARMA 09/12/07/14

Educational and Industri
212, the learned Judge has
to the DDA under Sectio
the petitioner as such w
possession was illegal an

7. This position wa
Division Bench of this Co
Development Authority &
(D.K. Jain, J.) was a mer
declaration under Sectio
that a policy decision
unauthorised colonies a
similar view has been
Roshanara Begum v. *Uni*
been upheld by the Supr
reported as 1997 (1) SC
cannot be oblivious of th
of which is sought to be
was in the list of the col

8. It is not a case of
the acquisition is challe
said land. Here is case w
existence. True that it
number of such coloni
addressing itself as to
Communication dated
Housing, Governmen
"Unauthorised colonie
had appointed a Com
respect of unauthorised
particular, before 15 J
decision in regard to th
report on 26 February,
was taken to regularis
We are concerned wit

"Colonies which
regularisation and wh

9. It is, thus, clear
of the colonies, in resp
which have been notif
the purpose of such re
take possession of the
issued on 11 Decemb
existence in earlier 70

494